the strength of its soft credit offer.

Once again, Italy's Snamprogetti* has proved that its name is weightier than merits when Government takes a decision.

MR. CHAIRMAN: It is only Government, not Rajiv Gandhi's Government.

SHRI ASHWANI KUMAR: Government headed by him.

MR. CHAIRMAN: No, the sentence will read as "Government" and not Rajiv Gandhi's Government. Why are you abdicating your right here? It is the Government.

SHRI ASHWANI KUMAR: For the South Bassein Phase II tender of ONGC (for platform erection work in sea), Snam's offer of $ 138 m. has been accepted and Hyundai's offer of $ 126 m. (lower by $ 12 m.) has been rejected. Even if the so-called 'soft loan' offer of Snam is taken into account, the net present value of Snam works out higher by more than $ 9 m. The 'soft' offer fails to soften the adverse offer of Snam by more than $ 3 m.

The decision-makers have let it out that South Korea's mounting adverse trade balance was influencing factor. This cannot be. The Commerce Ministry's published figures show that in 1983-84 adverse trade balance with Italy was Rs. 107 crores (minus) while it was only Rs. 58 crores (minus) with South Korea. But it is a technical point which is beyond all comprehension. The Government has rejected the tender of a Japanese concern for the South Bassein Phase I in 1985 on the ground of lack of experience of its fabrication sub-contractors, AGNP of Philippines on the ground of lack of requisite experience. But the very same rejected company has now been accepted by the Central Government now when they became the sub-contractors of Snamprogetti. Will the Government explain this anomaly, or is it a case of transparent mystery or a case of favouritism?

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): **

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*Reworded as ordered by the Chair.

**Not recorded.

REFERENCE TO THE REPORTED RESENTMENT AMONGST I.E.S. OFFICERS

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I want to draw the attention of the House to the growing resentment which is prevailing among the IES officers. Sir, this professional class I service was initially conceived by Pandit Jawaharlal Nehru and the service came into existence in 1961.

Sir, the cadre controlling authority has grossly mismanaged the affairs of the IES and till this date there has not been even a single cadre review. As a result the service conditions of IES officers are much worsen than most of the class II services even. This is evident from the fact that the officers of the first batch who were recruited in 1967 are still languishing as Deputy Directors whereas in all the other class I services the officers of the 1967 batch have risen to the rank of Joint Secretary. Sir, their stagnation is also clear from the fact that officers of the first 11 batches of the CSS class. II services are drawing the same salary—they are in the same pay scale—as the first 11 batches of the IES. As a result, the officers of this class I service have decided to launch an agitation. This is a very serious matter.

In view of this situation and the fact that inspite of repeated assur-

ances no cadre review has taken place till this date, I request the Government that immediate cadre review be ordered for the IES officers. Besides that, there should be a time-bound promotional pay scale pattern which is there in the case of other class I services. Also, the officers who were recruited in the 1973 batch have not yet been confirmed as permanent employees. The same may also be done. Thank you, Sir.

REFERENCE TO THE EXPLOSION INSIDE HANSALAYA BUILDING ON BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI AND ATMOSPHERE OF INSECURITY IN THE COUNTRY

श्री शरद यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, यहां से ठीक तीन किलोमीटर दूर हंसालय नाम की जो एक बड़ी बिल्डिंग है उसमें कल शाम को आठ बजे एक बम का एक्सप्लोजन हुआ । साढ़े आठ बजे के करीब वहीं पास में एक बारखंभा पर जाना है मैंने उससे इसके बारे में पूछा, क्योंकि पास ही एक टैक्सी स्टैण्ड है वहां से उसका ड्राईवर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि साथ ही की बिल्डिंग में एक बम फूट गया है । इस पर मैंने उसके बारे मे थाने में फोन किया और पूछा कि कहीं पर बम फूटा है और वह कैसे फूटा है इसके बारे में बताइये ? साढ़े आठ बजे के करीब जो वहां ड्यूटी पर आदमी था उसने कहा कि इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है । श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि पूरे देश की इस समय जो हालत है यानी असुरक्षा की हालत वह इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसका कहना ही क्या और उसके साथ जो दिल्ली है उसमें रोज कोई न कोई बैंक डकैती, कहीं बम फूटता हैं, कहीं पर दंगे होते हैं तथा जिस दिन दंगा चल रहा था कि वहां मुक्तसर में लोग मार दिये गये तो मैंने देखा कि उसके फोटो छपे थे सारे अखबारों मे, मैंने देखा कि मां अपने बच्चो को लेकर यहां से वहां दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही थीं और वर्किंग विमैन अपने बच्चों को दौड़ करके लेने के लिये जा रही थीं । मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे देश में आशंका इतनी अधि बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि देश में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं बची है । देश में जाति के नाम पर सेना बन रही है धर्म और मजहब के नाम पर सेना बन रही है । कहीं शिव सेना बन गई, वहीं खालसा सेना बन गई है और कहीं कोई सेना बन गई है ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Yadav, I gave you special permission to raise this matter...

श्री शरद यादव : श्रीमन्, मैं यही कहना चाहता हूं ।... (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : आपको मालूम होना चाहिये वहां पांच मिनट के अन्दर फोर्स पहुंच गई थी ।

श्री शरद यादव : मैं वही कहना चाहता हूं । अभी होम मिनिस्टर साहब का ध्यान हो रहा था । उन्होंने कहा कि इनकी यह पुलिस बढ़ गयी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है । पूरे देश का इंतजाम तो जैसा है, वैसा ही है, लेकिन दिल्ली में वेल इक्विपड साइंटिफिक इस्टूमेंट बढ़े हैं पुलिस फोर्स बढ़ी है, व्हीकल बढ़ हैं और यह सब बढ़ जाने पर भी पुलिस पर जनता को विश्वास नहीं है । लोगों में आशंका बढ़ती जा रही है, असुरक्षा बढ़ती जा रही है और जनता का सहयोग घटता जा रहा है । सब तरह का जो सरकारी तन्त्र है, चाहे जासूसी का हो या इंटलीजेन्स का हो, सब फेल होता जा रहा है और इस फेल होने के कारण पूरे देश की जनता में एक भय व्याप्त है, शंका व्याप्त है यानी सरकार का जो फर्ज है, सरकार की जो ड्यूटी है वह ऐसा लगता है कि कालैप्स हो गई है । इसलिये महोदय मैं चाहता हूं कि यह जो बम फटा है, इस पर माननीय होम मिनिस्टर साहब का बयान होना चाहिये और इस पर छोटी सी बहस भी करानी चाहिये । यही मेरा कहना है । धन्यवाद ।